Sixteenth Loksabha

an>

Title: Issue regarding water crisis in the country.

श्रीमती हेमामालिनी (मथुरा): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे एक अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। राइट टू एजूकेशन, राइट टू हैल्थ की तरह राइट टू वाटर की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत आज जल संकट के दौर से गुजर रहा है। देश की आजादी के बाद बिजली और सड़क के क्षेत्र में बहुत उन्नति होती जा रही है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देती हूं। लेकिन पानी को लेकर लोग बहुत तकलीफ महसूस कर रहे हैं। नीति आयोग के जल प्रबंध इनडेक्स के अनुसार 75 प्रतिशत घरों में पीने का पानी नहीं है। देश के करीब साठ करोड़ लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं और करीब दो लाख लोग इसी तरह मर भी रहे हैं। मैं जब अपने संसदीय क्षेत्र के गांव-गांव में जाती हूं तो महिलाएं आंखों में आंसू भरकर पीने के पानी की मांग करती हैं और मैं उन्हें दिलासा तो देती हूं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे उन्हें इस तकलीफ से बाहर निकाला जाए। रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक पानी की मांग उपलब्ध आपूर्ति से दोगुना हो चुकी होगी।

अंधाधुंध शहरीकरण के कारण, अनप्लांड अर्बनाइजेशन में उगते कॉन्क्रीट के जंगलों की वजह से ग्राउंड वॉटर सोर्सिस कम होते जा रहे हैं और समाप्ति की ओर जा रहे हैं, नदियों, धाराओं और तालाबों में रसायन और कचरा डालने की वजह से ग्राउंड वॉटर सोर्सिस कम होते जा रहे हैं और समाप्ति की ओर जा रहे हैं। नदियों, धाराओं और तालाबों में रसायन कचरा डालने की वजह से यह समस्या बढ़ रही है। सरकार ने दिखावटी सख्ती तो दिखाई है, लेकिन उसका कोई फायदा अभी तक नहीं हुआ है। जिस हालत में अभी हम देश को धकेल रहे हैं, उससे कल हमारा भी कोई शहर केपटाउन न बन जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। शिमला में यह प्रॉब्लम अभी होनी शुरू हो गई है और अभी है। जल संवर्धन और वॉटर कंजरवेशन के प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए, ताकि देश में सभी को शुद्ध पेयजल मिल सके।

माननीय अध्यक्ष:

श्री शरद त्रिपाठी,

भैरों प्रसाद मिश्र,

कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं

श्री रवीन्द्र कुमार जेना श्रीमती हेमामालिनी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।